



**UPSMA**  
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

# वार्ता The Dialogue

SEPTEMBER, 2025

Monthly Newsletter of UPSMA

VOL: III, ISSUE: 312

## NEWSMAKERS

### देश में चीनी उत्पादन में अग्रणी उत्तर प्रदेश की 122 चीनी मिलें



लखनऊ – उत्तर प्रदेश की 122 चीनी मिलों ने देशभर में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन कर राज्य को इस क्षेत्र में नंबर-1 बना दिया है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) ने इन मिलों के प्रतिनिधियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया।

इस बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. आर.पी. सिंह ने कहा कि चीनी उद्योग न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाता है, बल्कि यह लाखों किसानों और श्रमिकों को रोजगार भी देता है। इन मिलों का योगदान राज्य की GDP को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण है।

उन्होंने मिलों से आग्रह किया कि अब समय आ गया है कि उन्नत तकनीकों को अपनाया जाए ताकि उत्पादन के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन भी बना रहे। उन्होंने खासतौर पर तीन तकनीकों पर ज़ोर दिया:

- अपशिष्ट उपचार संयंत्र (Effluent Treatment Plant)
- उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली
- कम ईंधन खपत करने वाली तकनीकें

बोर्ड ने आश्वासन दिया कि वह उद्योगों को पर्यावरणीय नियमों का पालन कराने में सहयोग करता रहेगा और आवश्यक सुधारों पर काम करता रहेगा।

डॉ. यशपाल सिंह, जो यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन के तकनीकी सलाहकार हैं, उन्होंने शुगर मिलों की समस्याओं और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा लाए गए चार्टर 2.0 पर जानकारी दी।

लखनऊ के क्षेत्रीय निदेशक कमल कुमार ने चार्टर के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए मिलों से अनुरोध किया कि वे CPCB की वेबसाइट पर जाकर पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों की नियमित जांच करें और अपने सुझाव व शिकायतें लिखित में भेजें।

इस कार्यक्रम में अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें मुख्य पर्यावरण अधिकारी, तकनीकी सलाहकार और कानूनी अधिकारी शामिल थे।

अंत में बोर्ड की ओर से कहा गया कि भविष्य में भी इस तरह के संवाद जारी रहेंगे, जिससे उद्योग और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके।

Source: Sugar Times, 30<sup>th</sup> Aug, 2025

### सरकार ने चीनी मिलों और डिस्टिलरियों को ESY 2025-26 में बिना किसी प्रतिबंध के जूस/शुगर सिरप, बीएचएम और सीएचएम से एथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी

नई दिल्ली : भारत सरकार ने एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (E S Y) 2025-26 के दौरान चीनी मिलों और डिस्टिलरियों को बिना किसी प्रतिबंध के गन्ने के रस, शुगर सिरप, बी-हैवी मोलेसेस (बीएचएम) और सी-हैवी मोलेसेस (सीएचएम) से एथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी है। यह उपाय घरेलू खपत के लिए पर्याप्त चीनी उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए ईंधन में एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।



खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा चीनी मिलों और डिस्टिलरियों को जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि, चीनी मिलों और डिस्टिलरियों को ESY 2025-26 के दौरान बिना किसी प्रतिबंध के गन्ने के रस/शुगर सिरप, बीएचएम और सीएचएम से एथेनॉल उत्पादन की अनुमति है।

डीएफपीडी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के साथ समन्वय में, देश में चीनी के उत्पादन के साथ-साथ एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के उपयोग की समय-समय पर समीक्षा करेगा, ताकि पूरे वर्ष घरेलू खपत के लिए चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

Source: Chinimandi, 1<sup>st</sup> Sep., 2025

### जीएसटी युक्तिकरण से चीनी की मांग बढ़ेगी

नई दिल्ली : सकारात्मक उपभोग रुझानों और मजबूत उत्पादन संभावनाओं के चलते, भारतीय चीनी उद्योग निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर है। उद्योग का मानना है

Continued on the next page ...





**UPSMA**  
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

# वार्ता The Dialogue

SEPTEMBER, 2025

Monthly Newsletter of UPSMA

VOL: III, ISSUE: 312

कि, हालिया जीएसटी सुधार सही दिशा में एक कदम है जिससे मांग में तेजी आने की उम्मीद है। जीएसटी सुधारों पर टिप्पणी करते हुए, भारतीय चीनी एवं जैव ऊर्जा निर्माता संघ (ISMA) के महानिदेशक (DG) दीपक बल्लानी ने कहा कि परिष्कृत चीनी, सिरप और कन्फेक्शनरी उत्पादों को 5% जीएसटी स्लैब के अंतर्गत



लाने से खपत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कीमतों को युक्तिकरण से प्रसंस्कृत चीनी-आधारित उत्पाद अधिक किफायती बनेंगे, खासकर शहरी बाजारों में, जहाँ पैकेज्ड और ब्रांडेड उत्पादों की अधिक उपलब्धता के कारण मांग में लचीलापन अधिक होता है। हालांकि, ग्रामीण खपत को भी लाभ होगा, हालांकि अपेक्षाकृत धीमी गति से, क्योंकि पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की बढ़ती पहुँच और बढ़ती प्रयोज्य आय उपभोग के पैटर्न को नया रूप देने लगी है।

उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर, जीएसटी में कटौती से प्रसंस्कृत चीनी उत्पादों की घरेलू मांग में तेजी आने की संभावना है, उन्होंने कहा कि, भारत में चीनी की घरेलू खपत वर्तमान में लगभग 280 लाख टन सालाना है। हालांकि, आगे चलकर, हम चीनी की खपत में 1.5% से 2% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) की निरंतर वृद्धि की उम्मीद करते हैं, जैसा कि स्वतंत्र शोध अध्ययनों और उद्योग अनुमानों द्वारा उजागर किया गया है।

बल्लानी ने कहा कि, ISMA द्वारा 2025-26 के लिए जारी किए गए पहले प्रारंभिक अनुमान बहुत सकारात्मक हैं, और 2026-27 के बाद भी मजबूत संभावनाएँ हैं।

Source: Chinimandi, 06<sup>th</sup> Sep., 2025

## इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से तेल आयात पर कम होगी निर्भरता, प्रदूषण से मिलेगी राहत

पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण भारत में व्यावहारिक रणनीति के तौर पर उभर रहा है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। ई-20 पेट्रोल वाहनों की सेहत के लिए कितना अच्छा है या कितना खराब, यह जानने के लिए सबसे पहले तो यह समझना होगा कि आखिर यह



है क्या? इसे 80% सामान्य पेट्रोल और 20% इथेनॉल मिलाकर तैयार किया जाता है। इथेनॉल का उत्पादन गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से किया जाता है, जिनमें फसलों के अवशेष या पराली शामिल हैं।

भारत अपनी कुल जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। जाहिर है कि इथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा, तो आयात पर निर्भरता घटेगी और बिल कम होगा। इसे ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी अहम कदम माना जा रहा है। ब्राजील ने 1973 में ओपेक प्रतिबंध के कारण इथेनॉल की ओर रुख किया था। उस संकट ने एक लचीले ईंधन मॉडल को जन्म दिया, जो आज भी ब्राजील के लिए बड़ी सफलता बना हुआ है।

यह सुझाव भी दिया जाता है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाई जानी चाहिए। भारत में ऐसा ही हुआ है। पहले 5%, फिर 10 और उसके बाद 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की अनुमति दी गई। 2027 तक इसे 27 फीसदी करने का लक्ष्य है, हालांकि यह कोई सख्त सरकारी समय सीमा नहीं है। सरकार के विचाराधीन यह एक रोडमैप का हिस्सा है। बहस संतुलन के बारे में हो: विशेषज्ञों का मानना है कि असली बहस इथेनॉल बनाम इलेक्ट्रिक वाहन या खाद्य सुरक्षा बनाम ऊर्जा सुरक्षा पर नहीं होनी चाहिए। यह संतुलन के बारे में होनी चाहिए। भारत को शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों, 30 करोड़ आईसीई वाहनों के लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और कचरे को धन में बदलने के लिए 2जी इथेनॉल की जरूरत है। भारत स्थानीय वास्तविकताओं के अनुकूल इसके मिश्रण की मात्रा तय कर सकता है। यह व्यावहारिक भी है।

Source: Amar Ujala, 08<sup>th</sup> Sep., 2025

## खोई से बना ग्रेफिन, कपड़े-ड्रोन तक में होगा उपयोग

आईआईटी कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियर आकाश पांडेय और उनकी प्रतिभाशाली टीम के सदस्यों ने एक ऐसी देशी तकनीक विकसित की है, जो गन्ने की खोई से दुनिया के सबसे मजबूत नैनोमैटेरियल में से एक ग्रेफिन का निर्माण करती है। यह नवाचार सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव का पत्थर है।

इस नवाचार की सबसे चौंकाने वाली उपलब्धि है 'मल्टीस्पेक्ट्रल स्टील्थ टेक्नोलॉजी'। इस ग्रेफिन से बने टेक्सटाइल में छिपे इंसान, टैंक या हेंगर में खड़े एयरक्राफ्ट को थर्मल कैमरों और रडार की पकड़ में आना लगभग नामुमकिन है। यह तकनीक भारत को रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी बढ़त दिला सकती है और हमारे सैनिकों के लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच का काम कर सकती है।

मजबूत और कुशल ग्रेफिन आधारित मैटेरियल से बने ड्रोन और वाहनों की बाँडी न केवल 25 फीसदी तक अधिक मजबूत होती है, बल्कि वजन में भी हल्की होती है। इसी ग्रेफिन से बने हेलमेट और जैकेट 15 प्रतिशत तक अधिक मजबूत पाए गए हैं। यह टीम पहले भी पराली से बुलेटप्रूफ जैकेट बनाकर अपनी क्षमता साबित कर चुकी है





## UTTAR PRADESH'S FARM ECONOMY TRIPLES TO ₹7 TRILLION IN 8 YEARS

Uttar Pradesh's agricultural economy has seen impressive growth over the past eight years, expanding more than three times to reach nearly Rs.7 trillion in 2024-25, according to Agriculture Minister Surya Pratap Shahi. Back in 2016-17, the state's farm sector was valued at Rs. 2 trillion.

The surge is largely driven by increased food grain production, which now makes up over 40% of the state's agricultural output. Horticulture and sugarcane follow, contributing around 22.5% and 19.5% respectively. The rest comes from allied activities such as animal husbandry and fish farming.

The minister highlighted that the current food grain production in the state has reached 73.7 million tonnes, reflecting strong growth in the sector.

Source: Sugar Times, 27<sup>th</sup> Aug, 2025

## SCOPE OF SUGAR EXPORT IN NEW SEASON, MANAGING SUFFICIENT SUGAR STOCKS TOP MOST PRIORITY: ASHWINI SRIVASTAVA

Speaking at the India Sugar & Bio-Energy Conference in New Delhi, Ashwini Srivastava, Joint Secretary (Sugar), Department of Food and Public Distribution, said that in the new season of 2025-26, there will be scope of sugar export as it will have sufficient sugar stock, however, the quantity will be discussed. The carried forward sugar stock is expected at 5 MMT, and the sugar production is seen at 35 MMT. He expects sugar consumption at around 28 MMT in the new season.

In the current season, the Government allowed 1 MMT of sugar export, however about 0.8 MMT of export will take place in the next 2 weeks before the season ends.

Source: Chinimandi, 12<sup>th</sup> Aug, 2025

## U.P. TO BOOST ETHANOL PRODUCTION BY 12% IN 2025-26 PRIORITY: ASHWINI SRIVASTAVA

Lucknow: Uttar Pradesh is expected to increase its ethanol



production by over 12% in the upcoming ethanol supply year (starting November 2025), thanks to the central government's policy allowing ethanol to be made from sugarcane juice, syrup, and molasses.

This move not only helps reduce India's dependence on oil imports but also supports the country's ethanol blending programme aimed at improving energy security.

Currently, UP produces around 160 crore litres of ethanol across 90 distilleries. This is projected to rise to 180 crore litres, helping the state retain its position as India's top ethanol producer. However, in terms of total capacity, UP's 224 crore litre capacity still trails behind Maharashtra, which leads with 305 crore litres.

Ethanol prices range between ₹57.97 per litre (when made from C-heavy molasses) to ₹71.86 per litre (from maize).

Industry experts say that increasing ethanol production will help manage surplus sugar stocks and stabilise sugar prices. Since more sugarcane juice and molasses will be diverted to ethanol, sugar production will reduce slightly, which is expected to push up sugar prices by about ₹1 per kg—from ₹37-41 to ₹38-42 per kg.

Higher sugar prices will improve the financial health of sugar mills, enabling them to pay farmers on time and reduce dues. A senior official said this could bring more stability to UP's sugar sector, which is both politically and economically significant for the state.

Despite 25% of molasses being reserved for making country liquor (a key revenue source for the state), UP's ethanol output remains strong.

Meanwhile, sugarcane cultivation has expanded in the state—from 23 lakh hectares in 2022-23 to 29.5 lakh hectares in 2024-25. Average yield per hectare has also gone up from 79 to 83.25 tonnes.





**UPSMA**  
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

# वार्ता The Dialogue

SEPTEMBER, 2025

Monthly Newsletter of UPSMA

VOL: III, ISSUE: 312

However, the actual sugarcane crushed by mills dropped from 1,111 lakh tonnes in 2022-23 to 956 lakh tonnes in 2024-25. Sugar output also declined from 120.5 lakh tonnes to just over 92 lakh tonnes, due to more cane being used for khandsari (unrefined sugar), lower sugar recovery rates, and bad weather.

Source: Sugar Times, 04<sup>th</sup> Sep, 2025

## ESY 2024-25: AROUND 820 CRORE LITERS OF ETHANOL SUPPLIED DURING NOV 24-AUG 25



India is making significant progress in its Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme, with a marked increase in both ethanol production and blending rates.

According to the sources, during the current Ethanol Supply Year (ESY) 2024-25, Oil Marketing Companies (OMCs) received 820.52 crore litres of ethanol during November-August period.

So far in ESY 2024-25, ethanol supply from grains stands at 526.01 crore litres, while supply from sugar-based feedstocks stands at 294.51 crore litres.

India has successfully achieved 20% ethanol blending in petrol in 2025, five years ahead of its target, Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Puri recently announced.

This remarkable growth has helped reduce the country's dependence on imported crude oil, leading to a significant saving in foreign exchange.

In a relief for ethanol producers, the Indian government has

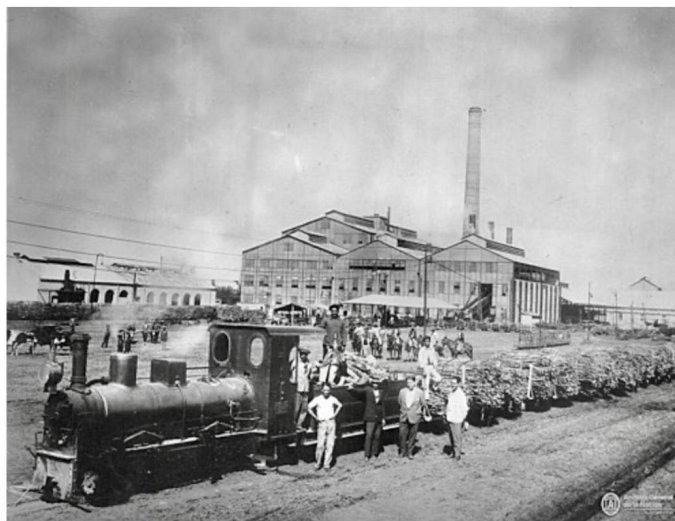
permitted sugar mills and distilleries to produce ethanol from sugarcane juice, sugar syrup, B-heavy molasses (BHM), and C-heavy molasses (CHM) during the Ethanol Supply Year (ESY) 2025-26 without any restrictions.

DFPD, in coordination with the Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG), will periodically review the diversion of sugar to ethanol production vis-a-vis production of sugar in the country so that availability of sugar for domestic consumption is ensured throughout the year.

Source: Sugar Times, 09<sup>th</sup> Sep., 2025

## Knowledge Box

### A Sugar Mill in Argentina



UPSMA Newsletter titled 'Varta' the Dialogue is providing information on sugar, sugar industry and sugar byproducts. We request you to share your thoughts and experience with us through write-ups, success stories, updates, photographs etc. We publish your creative in the next edition of this newsletter. You are requested to send your entries to be published in UPSMA newsletter through mail at [upsma@upsma.org](mailto:upsma@upsma.org). The newsletter will be uploaded on UPSMA website.

**अस्वीकरण:** यहाँ दी गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा या अन्य स्रोतों से ली गई है, जिन्हें विश्वसनीय माना जाता है और इस पर इस तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इस समाचार में दी गई जानकारी में किसी भी अनजाने त्रुटि से किसी भी व्यक्ति को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए 'वार्ता टीम' किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी। इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी इस समाचार की तारीख तक है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य के परिणाम या घटनाएँ इस जानकारी के अनुरूप होंगी।